धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही दी गई थी ;

(घ) क्या सरकार विदेशों से धनराशि प्राप्त करने की स्वतंत्रता के बावजूद निधियों के दुरूपयोग की संभावना को रोकने के लिये कानूनों में संशोधन करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण) : (क) से (ङ) 30-6-1993 को देश में कुल 14,683 एसोसिएशनें थी, जो विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पंजीकृत हैं । विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अंतर्गत, निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या समाजिक कार्यक्रम वाली एसोसिएशनें, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने के बाद, अथवा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकती हैं । धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्राप्त राशि में, धार्मिक स्थानों का निर्माण/विस्तार/रख-रखाव और मरम्मत, धार्मिक पुस्तकों इत्यादि का प्रकाशन, धर्म-प्रचारकों/पादरियों और धार्मिक समारोहों पर व्यय की जाने वाली राशि सम्मिलित है । 1990 में, एसोसिएशनों ने कुल 286.52 करोड़ रू॰ की राशि प्राप्त की है, जिन्होंने धार्मिक प्रयोजनों के लिए विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की सूचना दी है । उसमें से 107.10 करोड़ रू॰ धार्मिक प्रयोजनों के लिए थे । जबकि 1991-92 के लिए प्राप्त सूचना अभी भी अन्तिम है, 341.51 करोड़ रू॰ की कुल राशि में से 140.35 करोड़ रू॰ की राशि धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्राप्त हुई । जहां तक 1992-93 की सूचना का संबंध है, विभिन्न संबंधित एसोसिएशनों से, मई, 1993 को प्राप्त होने वाली रिपोर्टें सभी एसोसिएशनों से प्राप्त नहीं हुई हैं । चूककर्ताओं को अनुस्मारक भेजे गए हैं ।

2. विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है, ताकि उसकी खामियों को दूर किया जा सके । अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

कच्चे तेल का आयात

*409. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में कमी होने के कारण इन उत्पादों का आयात करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में इतनी कमी होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें तेल तथा प्राकृतिक गैस के भूतपूर्व अध्यक्ष की क्या भूमिका रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में कूड के वास्तविक उत्पादन एवं उसकी मांग के मध्य हमेशा अन्तराल होता है, कुछ समय से कूड तथा उत्पादों की जितनी मात्रा में कमी होती है उसका आयात किया जाता है ।

(ख) गत वर्षों के दौरान देशी कच्चे तेल के उत्पादन में होने वाली कमी के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :—

(1) बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र में किए जा रहे उपचारी उपाय ।

(2) गुजरात के कुछ क्षेत्रों में रिजर्वेयर संबंधी बाधाएं ।

(3) असम में कानून एवं व्यवस्था की समस्या ।

(ग) और (घ) अनेक नये तेल क्षेत्र विकास परियोजनाओं को स्वीकृत करने के अतिरिक्त, उत्पादन को अधिकतम करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि॰ द्वारा अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक उपाय किए गए हैं । देश में खोजे गए क्षेत्रों के विकास एवं तेल के अन्वेषण के लिए सरकार ने निजी भारतीय एवं विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित किया है ।

Increasing and Disturbing reports of pesticides destroying ozone layer

410. SHRI SOM PAL:

SHRI SARADA MOHANTY:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(4) whether Government are aware that there are increasing and disturbing reports of pesticides destroying ozone layer specially pesticides as reported in Food Commission, London of February, 1993 issue;

(b) whether any studies have been under-taken in the country on the subject and if so, the results thereof;

(c) whether the above pesticide will be banned;

(d) whether S. N. Banerjee Committee or any other Committee has recommended any action or alternative in the matter; and

(e) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE 'MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) According to the information available with Government, methyl bromide is a broad spectrum pesticide which is used worldwide for soil fumigation (80%), commodity and qurantine treatment (15%) and structural fumigation (5%). Scientific evidence, as reported, indicates that some methyl, bromide breaks down into nonvolatile substances which do not have emissions. Thus only part of methyl bromide use results in emissions that arise into the stratosphere thereby affecting the ozone layer.

The final report on the impact of methyl bromide on the ozone layer is to be completed by September, 1994 and the situation will be reassessed by the Montreal Protocol Ministerial level meeting in November, 1994.

(b) No, Sir

(c) Under the Montreal Protocol Methyl Bromide is not a controlled substance for developing countries.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Banning Trade in Tiger Bones

*411. SHRI SHIV CHARAN SINGH .

DR. NAUNIHAL SINGH:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal for banning trade in tiger bones and other parts, of tiger body, if so, the details thereof;

(b) whether Goverment are considering any proposal for Indo-Chinese protocol for ratification for tiger conservation, if so, the details thereof; and

(c) whether Government envisage any problem in the acceptance of this protocol, if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The trade in tiger bones and other parts of tiger body is already banned in this country.

(b) Yes Sir, to stop the illegal trade in tiger parts and tiger bones and also to engender worldwide publicity for eliminating such consumptive use of tiger products.

(c) No, Sir.

Development Plan for Western Railways

*412. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI:

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state what are the scheme wise details of Railway Development Plan for Western Railways convering Gujarat, Maharashtra and Rajasthan for the current year and the Eighth Plan period ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF):

Details of on going Western Railway works costing Rs. 5 Crores and above in the states of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra are as under:

S. No.	Name of the work	Estimated Cost	Allocation 1993-94	Targat Date of completion
	Gujarat			
1.	Nadiad-Modassa & Modassa-Kapadvanj new line (60.5 Km.)	Rs. 30.00 Cr.	Rs. 1.000	Frozen
2.	Godhara-Indore via Dahod, Sardarpur, Dhar and between Dewas-Maksi new Line (316 Km.) (part in Gujarat)	Rs. 297.14 Cr.	Rs. 1.00 Cr.	31-12-96 for Dewas-Maksi portion
3.	Viramgam-Jodhpur direct BG rail link & Bhildi-Viramgam gauge conversion & new line.	Rs. 155.66 Cr.	Rs. 0.33 Cr.	Frozen